

क्या बंगाल में भाजपा का “ट्रंप कार्ड” साबित होंगे नए अध्यक्ष नितिन नबीन

बंगाल में भाजपा ने “भद्रलोक” (जिसमें कायस्थ अधिक हैं) वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पश्चिम बंगाल में एक “ट्रम्प कार्ड” के रूप में उभरेंगे, जहाँ कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं।

बिहार चुनावों के सबक पश्चिम बंगाल में भाजपा के काम नहीं आयेंगे। बिहार में एनडीए ने महागठबंधन के खिलाफ 0.1 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर के साथ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, जबकि पश्चिम बंगाल में 2021 के पिछले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का वोट शेयर 10 प्रतिशत अधिक था। बिहार में भाजपा की सफलता में छोटे दलों, जिनमें एलजेपी (आरबी) शामिल है, के साथ गठबंधन का बड़ा योगदान था, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ

- बंगाल में हालांकि भद्रलोक के वोटर्स की संख्या कम है पर वे आम वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं। बंगाल की कई नामचीन हस्तियां इसी वर्ग से आती हैं, जैसे, स्वामी विवेकानन्द, अरबिंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास, ज्योति बसु, सत्यजित रे, बिमल मित्र आदि।
- बिहार में भाजपा के गठबंधन एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन में मात्र 0.1 प्रतिशत का वोट अंतर था पर बंगाल में तृणमूल का वोट शेयर भाजपा से 10 प्रतिशत अधिक है। बिहार के विपरीत यहां भाजपा को छोटे-छोटे दलों का सहारा भी नहीं है।
- सवाल यह है कि क्या भद्रलोक को साधकर भाजपा तृणमूल के आसपास पहुंच पाएगी?

केवल वामपंथी और कांग्रेस ही अन्य प्रमुख दल हैं, तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के भी छोटी-मोटी संख्या में ही चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। ममता

बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की महिला वोटर्स पर काफी मजबूत पकड़ है। तो, भाजपा इन चुनौतियों से कैसे काबू पायेगी।

जाहिर है, भाजपा का सबसे अच्छा विकल्प, टीएमसी के साथ ही, वामपंथी और कांग्रेस के मूल समर्थन आधार को साधना है और उन ‘भद्रलोक’ वोटर्स की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना है, जो संख्या में कम होते हुए भी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही वह जगह है, जहाँ नबीन, जो कि कायस्थ जाति से हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका की उम्मीद है।

बंगाल के कायस्थ, जो शिक्षित और प्रभावशाली हैं, अपनी प्राचीन परंपरा पर गर्व करते हैं। जाने-माने बंगाली कायस्थों में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ज्योति बसु, चितरंजन दास, सत्यजीत रे, बिमल मित्र, जैमिनी राय, अमर्य सेन और सर जदुनाथ सरकार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि नये कार्यकारी अध्यक्ष, अपने जमीनी दृष्टिकोण के साथ, इस वर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग की सफलता के बीच गडकरी फिर विवादों में

उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप है कि ऐथनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटों को व्यवसायिक लाभ पहुंचाया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भारत की 20 प्रतिशत ऐथेनॉल मिश्रण नीति (ई 20) को लेकर एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। यह विवाद मुख्य रूप से हितां के टकराव के आरोपों, वाहनों के प्रदर्शन से जुड़ी चिंताओं और राजनीतिक विरोध पर केन्द्रित है।

उन पर लगाए गए प्रमुख आरोपों में सबसे अहम हितां के टकराव का है। सितंबर 2025 में कांग्रेस पार्टी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी ने सरकारी नीति का इस्तेमाल अपने परिवार के व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए किया।

आरोपों के अनुसार, उनके बेटे निखिल गडकरी द्वारा संचालित सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की आयवित्त वर्ष 2024

- एक विवाद यह भी है कि ऐथेनॉल युक्त पेट्रोल-डीज़ल से वाहनों के इंजन खराब हो रहे हैं और वाहनों का माइलेज भी घट गया है।
 - लेकिन नितिन गडकरी इन सभी आरोपों से इनकार करते हैं, उनका कहना है कि पेट्रोल लॉबी पैसे देकर उनके खिलाफ यह दुष्प्रचार करवा रही है।
- की पहली तिमाही में 17.47 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 510 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।
- इसी तरह, उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी द्वारा संचालित मानस एगो इंडस्ट्रीज भी ऐथेनॉल सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) की एक बड़ी कंपनी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि ई20 ईंधन को पूरे देश में तेजी से लागू किए जाने के कारण इन कंपनियों को असाधारण मुनाफा हुआ।
- वाहनों के प्रदर्शन को लेकर भी

वनरक्षक पेपर लीक में लेखाकार व वनरक्षक गिरफ्तार

जयपुर, 22 दिसंबर। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीबाड़े के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने वनरक्षक भर्ती-2020 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, पेपर पढ़ने वाले लेखाकार सहित वनरक्षक को गिरफ्तार किया है। अब जाकर एसओजी की जांच में खुलासा हुआ है कि उदयपुर व बांसवाड़ा के अलावा जयपुर में भी वनरक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ

- एसओजी ने अपने घर पर लीक पेपर पढ़वाने वाले वनरक्षक तथा लीक पेपर पढ़कर वनरक्षक की नौकरी हासिल करने वाले को गिरफ्तार किया।

था। जयपुर में एक लेखाकार ने अपने घर पर वनरक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़वाया था। इसके बाद एसओजी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लेखाकार सहित, लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने वाले वनरक्षक को पकड़ा है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी साले-बहनोई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के पिछले दिनों गिरफ्तार मुख्य आरोपी जबराम से पूछताछ में पता चला कि टोडाभीम निवासी लेखाकार अमन जोरवाल ने जयपुर में अपने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

घोषणा के साथ ही झटका लगा भारत न्यूजीलैंड ट्रेड डील को

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “बैड डील” करार दिया

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 22 दिसंबर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन द्वारा बड़े जोर-शोर से घोषित मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट – एफटीए) को एक उस समय एक तगड़ा झटका लगा, जब सत्ताधारी गठबंधन के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इसे “खराब समझौता” करार देते हुए कहा कि यह “बहुत अधिक देने” तथा “बहुत कम” प्राप्त करने वाला समझौता है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते को स्वीकरण एक टेलीफोन कॉल के दौरान किया, जो द्विपक्षीय, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के एक बड़े विस्तार का संकेत देता है। इस समझौते पर तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद

है और 2026 में यह क्रियान्वित हो जायेगा।

दोनों पक्षों ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी बताया, और यह भारत-न्यूजीलैंड एफटीए रिकॉर्ड नौ महीने में पूरा हो गया। इस समझौते की विधिवत बातचीत पीएम लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान शुरू हुई थी।

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री पीटर्स ने न्यू दिल्ली और वेलिंग्टन के बीच हुए इस एफटीए का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व वाली सरकार ने डील में “सबस्टैस” का ध्यान नहीं रखा और शीघ्र डील होने पर ध्यान रखा।

पीटर्स, जो “न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी” के नेता और सरकार में गठबंधन साझेदार हैं, ने कहा कि उनकी पार्टी “खेद सहित” इस समझौते के खिलाफ

- विंस्टन पीटर्स ने कहा, इसमें न्यूजीलैंड को बहुत कुछ देना पड़ेगा पर बदले में उसे बहुत कम मिलेगा। पीटर्स न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता हैं, जो न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार का हिस्सा है।
- भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने टेलिफोन वार्ता में इस डील की घोषणा की। इस डील पर तीन माह के भीतर हस्ताक्षर होने और इसके 2026 में क्रियान्वित होने की संभावना है।

है और जब यह संसद में पेश होगा तो वे इसके सक्षम कानून का रूप लेने के खिलाफ मतदान करेंगे।

पीटर्स ने एक्स पर लिखा, “हम भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते को न तो मुक्त मानते हैं और न ही निष्पक्ष।” उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के आर्थिक और श्रमिक हितों

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

पीटर्स ने कहा, “प्रति व्यक्ति आधार पर, राष्ट्रीय सरकार ने न्यूजीलैंड के श्रम बाजार में भारत को कहीं अधिक पहुंच दे दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ने अपने को सुरक्षित करने के लिए नहीं दी थी। यह न्यूजीलैंड के वर्तमान श्रम बाजार की स्थिति को देखते हुए यह बेहद अव्यावहारिक है, जहां बहुत से न्यूजीलैंडवासी बेरोजगारी या आर्थिक रूप से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।”

उन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा सुचित के बारे में भी चिंता जताई।

उन्होंने कहा, खासतौर से भारत के नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीजा बनाने से न्यूजीलैंड में भारतीय आप्रवासन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है जबकि हमारा श्रम बाजार पहले से ही बहुत तंग है।”

मोर का शिकार कर पार्टी करते ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार

उदयपुर, 22 दिसम्बर (कासं)। जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला गडावत गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक रूपलाल पुत्र प्रेमशंकर मीणा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष है तथा दूसरा हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल पुत्र भगवान मीणा है, तीसरा आरोपी राकेश पुत्र कुरीचंद है। तीनों ही आरोपी एक गांव के हैं।

प्रकरण के अनुसार, रविवार को गश्त के दौरान एएसआई रमेशचन्द्र को ऋषभदेव थाना क्षेत्र बिलख फला

- श्रृषभदेव थाना पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल प्रेम शंकर मीणा के साथ एक हिस्ट्रीशीटर अर्जुनलाल मीणा को भी पकड़ा।

गडावत गांव में नदी किनारे किसी जानवर का शिकार कर पार्टी करने के लिए पकाने की सूचना मिली। इस पर टीम मौके पर पहुंची। जहां तीनों आरोपी शिकार किए गये राष्ट्रीय पक्षी मोर को पकाते मिले। तीनों को दबोचकर तथा इनके कब्जे से शिकार किए मोर के अवशेष जब्त कर, पूछताछ के लिए थाने लेकर आए।

वन विभाग अधिकारियों को सूचना देने पर वनरक्षक सुमित्रा ने मौके पर पहुंच आवश्यक कार्यवाही शुरू की। इधर इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऐथनॉल ब्लैंडिंग में 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल, भारत की बड़ी उपलब्धि

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपलब्धि तय समय से 5 साल पहले ही प्राप्त कर ली गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर। भारत को ऐथेनॉल ब्लैंडिंग कार्यक्रम में 20 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्त तय अवधि से पांच साल पहले ही हो गई है, जिससे कच्चे तेल के आयात व्यय में कटीती हुई है और यह सतत ईंधन परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत के प्यूल पंपों पर दशकों की सबसे बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया चल रही है। देश का ऐथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम पायलट चरण से राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है, जिसमें ऐथनॉल सप्लाई इयर (ईएसवाय) 2024-25 में ब्लैंडिंग औसतन 19.24 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और ईएसवाय 2025-26 में ई 20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथनॉल का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है।

पिछले पांच वर्षों में, ब्लैंडिंग

- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीज़ल) से इकोफ्रेंडली ईंधन के इस्तेमाल की तरफ जाने की दिशा में यह बड़ी सफलता है।
- ऐथेनॉल उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर है वहीं स्थान पर यूएसए तथा दूसरे पर ब्राज़ील है।

8.10 प्रतिशत से बढ़कर ईएसवाय 2020-21 में 14.60 प्रतिशत तक पहुंच गई, जब 707.40 करोड़ लीटर ऐथनॉल पेट्रोल में मिलाया गया। बिल्कुल हाल ही में ईएसवाय (नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक) में, 1,022.4 करोड़ लीटर ऐथनॉल मिलाया गया, जिससे औसतन 19.24 प्रतिशत की ब्लैंडिंग हासिल हुई, जो ई 20 लक्ष्य के बेहद करीब है।

यह जानकारी 8 दिसम्बर 2025 को राज्य सभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी

ऐथेनॉल ब्लैंडिंग भारत को विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) की बचत में भी मदद कर रहा है, क्योंकि यह कच्चे तेल के आयात बिल को कम कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 दिसम्बर 2025 को संसद में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में ऐथेनॉल ब्लैंडिंग की वजह से देश ने 1,55,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत की है।

इन लाभों के बावजूद, और 2024 में 6.2 बिलियन लीटर ऐथनॉल का उत्पादन करने के बावजूद, भारत अभी भी वैश्विक नेताओं, अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे है, जैसा कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों से पता चलता है।

वैश्विक ऐथेनॉल उत्पादन में अमेरिका की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत (61.4 बिलियन लीटर) है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी।

लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी। यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 बनाया। 2009 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है।

नरेगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 40 प्रतिशत से अधिक न हो एवं 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 10 प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत से भी कम भुगतान पड़ता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं। कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंगे सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंगे गाड़ी खरीद ली थी। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था। सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2009 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 15 दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित कराया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजाम में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरी में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल

जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेगा के अंतर्गत देश में कुल 15.5 करोड़ जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 200 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 100 दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 45 दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 125 दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2015 में संसद में नरेगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 10 वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संसथा बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं। वह इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे? अब तक राज्यों पर 10 प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पड़ता था जो बढ़कर अचानक 40 प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि श्रष्टों को तोड़ मरोड़ करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख-राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू-राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों की केंद्रीकरण कर दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है। इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 700 किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थाओं द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा।

वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस 500 मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है और इस क्षेत्र में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है और यही भौगोलिक और कानूनी तथ्यों से प्रमाणित है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने स्पष्ट सिफारिश की कि जब तक इंडियन कार्टिसिल ऑफ फॉरस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। इस योजना में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कहां खनन पूरी तरह वर्जित रहेगा, कहां सीमित अनुमति दी जा सकती है और किन क्षेत्रों में पुनर्बहाली प्राथमिकता होगी। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य खनन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियंत्रण स्थापित करना है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों की कसौटी पर नितांत तथ्यहीन हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कार्यकाल में अरावली के लिए दोस संरक्षण मॉडल विकसित किया जा सकता था, तब कोई निर्णायक पहल नहीं हुई। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सख्त, वैज्ञानिक और

पारदर्शी ढांचा लागू हो रहा है, तब उसी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा करना जनभावनाओं को भ्रमित करने का प्रयास है।

सरकार की नीति केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। जून 2025 में शुरू की गई अरावली ‘ठीन वॉल’ परियोजना इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। चार राज्यों के 29 जिलों में पांच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाकर 2030 तक करोड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल बताती है कि सरकार अरावली को केवल बचाने नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करना चाहती है।

अरावली प्रकरण में वास्तविक संघर्ष पर्यावरण और विकास के बीच नहीं, बल्कि तथ्य और भ्रम के बीच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और केंद्र सरकार की नीति यह स्पष्ट करती है कि अरावली के संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वर्षों से चली आ रही अस्पष्टताओं को समाप्त कर एक वैज्ञानिक, न्यायिक और जवाबदेह ढांचा स्थापित किया गया है।

आज आवश्यकता है कि अरावली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति तथ्यों के साथ खड़ी हो, क्योंकि अरावली का प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

814वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री दोरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का व्यैय सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है और उसी भावना के साथ यह संदेश भी दरगाह के जरिए देश तक पहुंचता है। उन्होंने बताया कि अजमेर में केंद्रीय मंत्री रिजिजू का स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई कुछ भी कहे हमारे देश को कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा आबादी वाला देश हिंदुस्तान है। चीन के भी आगे हम निकल गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक साथ आगे चलना है।

2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु,

■ केंद्रीय मंत्री रिजिजू लेकर पहुंचे अजमेर, बुलंद दरवाजे पर पीएम का संदेश पढ़कर सुनाया

एसपी वंदिता राणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चित्ताग पासवान की ओर से चादर पेश की गई। यह चादर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद साबिर ने पेश की। दरगाह के खादिम जुहर बाबा चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई। जियारत के बाद अकीदत और सम्मान के साथ चादर दरगाह शरीफ में पेश की गई। दरगाह कमेटी के नाजिम बिलाल खान ने बताया कि तेरा सदी के मद्देनजर विश्रामस्थली में ठहरने वाले जायरीन की सुविधार्थ हेतु माकूल इंतजाम किए गए हैं, वहां दुकानें लगाया शुरू हो गई हैं, साथ ही विश्राम स्थली पर ठहरने वालों के लिए अकीदतमय ने लंगर शुरू कर दिया है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों के अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। छह दिवसीय उर्स में आने वाले अधिकांश जायरीन उर्स की छटी का कुल की रस्म अदा कर ही लौटेंगे।

जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं। इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एग्म में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिबर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिबर दिल्ली भेजा गया है।

एग्म के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिडा के रहने वाले भोमाराम (5) पुत्र भैराराम को बार-बार दौर पड़ने की समस्या पर 15 दिसंबर को एप्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

■ पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिबर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्पेटिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग

में बार बार दौर पड़ने से भोमाराम ब्रेन डेड हो गया। इसके बाद परिवार को ऑर्गन डोनेट करने के बारे में बताया गया। इस पर परिजन सहमत हुए और उसके बाद सोमवार सुबह ऑर्गन डोनेशन करने के बाद बाँडी परिजनों को सुपुर्द की गई। उसका एक लिबर फ्लाइट से आईएलबीएस दिल्ली भेजा गया, जबकि उसकी दो किडनी जोधपुर एग्म में ही एडमिट मरीज को

लगाई गई। एग्म के अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि इस अंगदान से दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। ट्रांसप्लांट के नोडल अधिकारी दो शिवचरण ने बताया कि ऑर्गन डोनेट करने के बाद पांच से छह घंटे में लगाया जरूरी होता है, इसलिए लिबर को फ्लाइट के जरिए दिल्ली भेजा गया।

राशिफल मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025
पौष मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, श्रवण नक्षत्र बुधवार प्रातः 6:08 तक, व्याघात योग सायं 4:30 तक, गर करण दिन 12:13 तक, चन्द्रमा आज मकर राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-धनु, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज रवियोग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। भद्रा रात्रि 12:42 से आरम्भ होगी। आज अंगारक चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:51 से 11:08 तक, लाभ-अमृत 11:08 से 1:43 तक, शुभ 3:00 से 4:18 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 7:17, सूर्यास्त 5:35 तक

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुसमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।	सिंह विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	धनु आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संचावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उसव जैसा माहौल रहेगा।
वृष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संचावित खोत से धन प्राप्त होगा।	कन्या व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।	मकर मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक खर्च पर नियंत्रण रहे।
मिथुन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।	तुला घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	कुंभ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अंगर्गत कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
कर्क परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।	वृश्चिक परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	मीन अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मार्गलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।



सार-समाचार

स्कूटी सवार महिला ट्रक के नीचे दबी, मौत

बीदासर (निस)बीदासर गोपालपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर कस्बे के केके हार्डवेयर के पास सोमवार की दोपहर स्कूटी सवार महिला की ट्रक के निचे दबने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीदासर तहसील के गांव बालेरा की 27 वर्षीय सुशिला मंडा स्कूटी लेकर बीदासर बाजार से घरेलु सामान खरीदकर वापस अपने गांव जा रही थी, कि ट्रकर रोड पर एक बिना नंबर प्लेट के मूंगफली की बोरियों से भरे ट्रक के निचे दबने से महिला की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ घटना स्थल पर जमा हो गई, तथा वाहनों की कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव राजकीय सीएचसी में पहुंचाया। वही मृतका के देवर सुरेंद्र ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि मेरी भाभी बीदासर से घरेलु सामान खरीद कर स्कूटी से वापस गांव बालेरा आ रही थी कि ट्रकर रोड पर बिना नंबर के ट्रक के वाहन चालक वाहन को लहराता हुआ तेज गति व गफलत से चलाते हुए स्कूटी के टक्कर मारी जिससे मेरी भाभी की ट्रक के निचे आने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतका के देवर सुरेंद्र की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन व चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सरकारी अस्पताल में मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद वाहन चालक मौके पर ही वाहन को छोड़कर फरार हो गया। मृतक महिला के दो पुत्र हैं।

140 छात्राओं को स्वेटर वितरित की

चूरू (निसं)। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा चूरू द्वारा स्वर्गीय ताराचंद मरदा की स्मृति में शरद मरदा, मरदा सेवा ट्रस्ट चूरू के सौजन्य से राजकीय सर्व हितकारी बालिका उमावि चूरू की 140 छात्राओं को स्वेटर वितरण की गई। कार्यक्रम संयोजक जगदीश शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर समसा एडीपीसी सरिता आत्रेय, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चूरू बृजेंद्र दाधीच, रेडक्रॉस सोसायटी सचिव रघुनंदन शर्मा, उपाध्यक्ष श्याम सुन्दर शर्मा, छतरसिंह डागा, बालकृष्ण बंशिया, सुनील भाउवाला के आतिथ्य व प्रधानाचार्य अमरसिंह कस्वां की अध्यक्षता में स्वेटर वितरित की गई। सर्वप्रथम मां सरस्वती के समकक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा चूरू के श्याम सुंदर शर्मा ने संस्था के सेवा कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मरदा सेवा ट्रस्ट चूरू द्वारा सरकारी विद्यालयों में स्वेटर वितरण कर पुण्य का कार्य किया है। सरिता आत्रेय ने भामाशाह एवं रेड क्रॉस का धन्यवाद ज्ञापित किया।

ट्रामाडोल टेबलेट के साथ युवक गिरफ्तार

बीदासर (निसं)। नशे के खिलाफ बीदासर पुलिस व एएनटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए रविवार की रात्रि में ट्रामाडोल टेबलेट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर बीदासर निवासी वैभव सुंदरीया को अवैध नशीली टेबलेट ट्रामाडोल के साथ गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 हजार 4 सौ गोलियों को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सोमवार को गिरफ्तार किए गए युवक को न्यायालय में पेश करने पर दो दिन की पीसी रिमांड पर भेजा।

जरूरतमंद की सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है : राठौड़

चूरू, (कासं)। राजनीति जब सेवा का माध्यम बने इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना हो तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की राजनीति को देखा जा सकता है, जिनका एक मात्र ध्येय गरीब की सेवा करना है। प्रकरण था, बनवारीलाल धानक गांव पुनरास तारानगर चूरू के पुत्र सोहनलाल एवं कृष्ण कुमार एवं पौत्र संजय कुमार की लगभग दो वर्ष पूर्व नहर में डूबने से मृत्यु हो गई थी परंतु कोई पोस्टमार्टम नहीं होने से मामला फंस गया और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होने से सरकारी सहायता से वंचित था। जब इस बात से एस सी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीता राम लुगरिया ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को अवगत करवाया तो उन्होंने पंडित परिवार की व्यथा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने रखी। राजेन्द्र राठौड़ एवं जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर सहायता राशि देना स्वीकृत किया। प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिजन सावित्री

देवी पत्नी बनवारीलाल धानक को दो दो लाख रुपए का चेक एवं मुकेश देवी पत्नी कालुराम धानक को दो लाख रुपए का चेक राजेन्द्र राठौड़ एवं विधायक हरलाल सहारण, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने प्रदान किया। इस पर पंडित परिवार ने राजेंद्र राठौड़ को गरीबों का मसीहा बताया। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जिस प्रकार प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार है, उस सरकार से हर आम व्यक्ति को आशा है और जब मुख्यमंत्री को पता लगा इस समस्या के बारे में तो उन्होंने गरीब की सहायता करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता सीताराम लुगरिया ने जब मुझे इस बारे में अवगत करवाया कि इस गरीब परिवार का सहारा छीन गया है तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वार्ता कर

उनको यह सहायता दिलवाई है। इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि गरीब को गोपेश मानकर कार्य करना पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की राजनीति का हिस्सा रहा है। इस पर एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया ने आभार जताते हुए कहा कि यह धनराशि इस परिवार के लिए भरण पोषण के लिए उपयोगी साबित होगी। इस राशि से इनके बिछड़े हुए परिजन तो नहीं मिल सकेंगे लेकिन इससे इन्हें जीवन यापन में सहायता मिल सकेगी। इस अवसर पर जिला महामंत्री चंद्रा राम गुरी, पूर्व प्रधान विक्रम कोटवादा, युवा नेता अभिषेक चौटिया, पूर्व जिला उप प्रमुख महेंद्र न्योल, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश नाई, संत कबीर शिक्षा समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह धानक, जिला मंत्री सतार खान, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, रवि दाधीच, राजीव शर्मा, नीरज जांगिड, निजजू नाई सहित अनेक लोग रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया

चूरू (निसं)। जिला मुख्यालय पर केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने, महात्मा गांधी के नाम को हटाने तथा रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने की साजिश के विरोध में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अध्यक्ष व सुजानगढ विधायक मनोज मेघवाल की अध्यक्षता में चूरू जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आपणी योजना के सामने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि कोई महात्मा गांधी

से नफरत कर सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा से नहीं, उनकी विचारधारा आज भी दुनिया के हर कोने में गरीब और मजदूरों की आवाज है। कस्वां ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। आने वाले दिनों में लगातार वाडों, ब्लॉकों में प्रदर्शन करेंगे, इस आंदोलन को ग्रासरूट लेवल तक लेकर जाएंगे। चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सुजानगढ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की चेरपर्सन थी तब देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए यह नई योजना

लाई गई थी। देश के किसानों और गरीब आदमी को रोजगार देने के लिए यह बेमिसाल योजना लाई गई थी जिसका नाम महात्मा गांधी मनरेगा योजना था। आज भाजपा सरकार इस योजना को खत्म करना चाहती है जिसको हम कभी नहीं करने देंगे। सादुलपुर की पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार ऐतिहासिक योजना मनरेगा को मिटाने पर तुली है। भाजपा सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर न केवल उनकी विरासत पर हमला कर रही है, बल्कि ग्रामीण मजदूरों के कानूनी अधिकार को भी छीन रही है।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ

चूरू (निसं)। बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजकीय लोहिया महाविद्यालय प्राचार्य डॉ मंजू शर्मा, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के जिला समन्वयक महेंद्र कुमार खारडिया, प्रबंध समिति के संयुक्त सचिव राजेश भावसिंहका, प्रबंध समिति के सदस्य श्यामसुंदर शर्मा द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया।

दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि डॉ मंजू शर्मा ने छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य को अपनाकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के जिला समन्वयक महेंद्र कुमार खारडिया ने छात्राओं को एन.एस.एस. की गतिविधियों से सहकारिता भाव सिखते हुए निरंतर सुजनात्मकता उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया।

साथ ही उन्होंने डिजिटल साक्षरता का महत्व बताते हुए स्वयं को जागरूक होने के साथ-साथ समाज को

जागरूक करने का संदेश दिया। सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी से करने, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान वार्तालाप से करने, अपने परिजनों के अनुभवों का लाभ लेने और संस्कार के भाव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य आशा कोठारी ने राष्ट्रीय सेवा योजना को व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम बताया उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना छात्राओं में सहकारिता भाव को जागृत करता है। उन्होंने कहा की सेवा वो प्रकल्प है, जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती।

कार्यक्रम अधिकारी कविता पंसारी ने विशेष शिविर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ललिता मंडावेवाला, मीना भावसिंहका आदि अतिथि भी पधारे। छात्रा मनीषा सैनी, साक्षी व्यास, यशवंती, मुस्कान आदि ने राष्ट्रीय सेवा योजना लक्ष्य गीत प्रस्तुत किया।

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

चूरू संभाग, चूरू

क्रमांक-सनि./स्कूल शिक्षा/चूरू/लेखा/शै.प्र./2025-26/105

दिनांक-18.12.2025

शैक्षणिक भ्रमण ई-निविदा संख्या 01/2025-26

एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत चूरू संभाग के लगभग 150 विद्यार्थियों के दल को अन्तर्राज्यीय शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाना है। इस हेतु IRCTC/ पंजीकृत सेवा प्रदाता/राजस्थान पथ परिवहन निगम से शैक्षणिक भ्रमण हेतु परिवहन, भोजन, आवास, स्थानीय परिवहन व अन्य समस्त व्यय हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

UBN NO. EDU2526SLOB00104

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)

चूरू संभाग, चूरू

आरोग्य मेला 25 से

चूरू (निसं)। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और हॉम्यो विभाग की ओर से सप्तागीय स्तर पर चार दिवसीय मेले की तैयारी को लेकर सोमवार को आयुर्वेद विभाग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

डॉ. सत्यवीर सिंह अतिरिक्त निदेशक, नोडल अधिकारी, बीकानेर ने बताया कि मेला 25 से 28 दिसम्बर तक पुलिस लाईन मैदान में आयोजित होगा। मेले को लेकर लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मेले के दौरान रोजाना सुबह 7 से साढ़े 8 बजे तक योगाभ्यास करवाया जाएगा।

इसके बाद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेषज्ञों की ओर से निःशुल्क औषधि वितरण और औषधि वितरण के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला काढा पिलाया जाएगा। साथ ही दोपहर 12 बजे से स्वास्थ्य विषयक प्रश्नोत्तरी का आयोजन होगा, जिसमें प्रश्न के उत्तर देने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त

(द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम

1959 की धारा 23 के अर्धीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुख्यमा नम्बर 39/2025
(नाम, वर्ण तथा निवास स्थान)
तुम्हें श्री शशी कान्त मोदी पुत्र स्व. श्री एस.एन. मोदी निवासी 203 अग्रस निवास सरोजनी रोड रामकृष्ण भिमान मार्ग कोटाकुज केरत मुरबं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रत्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रत्यास श्री सत्यनारायण सागर मल मोदी एम्युकेलन ट्रस्ट इंडोरु स्थला भवन खीचड हॉस्पिटल क सामने नवलगढ रोड सीकर मे न्यास के न्यासी श्री सत्यनारायण जलान की मृत्यु श्री नयनकान्त मोदी का त्याग पत्र व मृत्यु श्रीमती प्रेमलता सुर्यकान्त मोदी की मृत्यु श्री ऋषि कुमार बरसिवा की मृत्यु होने से उनका नाम ट्रस्टी पद से हटाने की प्रार्थना करने व उनके स्थान पर श्री श्रीराम सुर्यकान्त मोदी श्री प्रियंक शांतिव्रत मोदी श्रीमती कल्पिता संभव मोदी को नवीन प्रत्यासी लिए आकम् प्रत्यासियों में हूये परिवर्तन को दर्ज अभिलेख हेतु जानें किये जाने के लिए प्रपत्र-8 मे आवेदन पत्र दिया जाँ।
अतएव धारा 23 मे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रत्यास मे हूये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रत्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियाँ, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निरिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं तो उक्त आवेदन पत्र निरिस्ट रीति से निर्गमित किया जाएगा तथा जांच प्रसित मामले मे निष्पत्ति अभिलिखित किया जाएगा।
आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अर्धीन जारी किया गया।
आपदा तारीख पेची 30.12.2025

सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कोर
अदालत



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



2 साल

नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान - हमारा राजस्थान



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
₹2,000 + करोड़ की स्वीकृति

राज्य परियोजनाओं से कृषकों
को ₹1,200 करोड़ का हस्तांतरण

मुख्य अतिथि

श्री शिवराज सिंह चौहान

माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

अध्यक्षता

श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

नागौर जिले में ₹351 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

राशि हस्तांतरण

कृषि एवं उद्यानिकी योजनाएं

31,600 कृषकों को ₹200 करोड़

कृषि आदान-अनुदान

5 लाख कृषकों को ₹700 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

18,500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना

4.50 लाख पशुपालकों को ₹200 करोड़

23 दिसम्बर, 2025 | अपराह्न 12:00 बजे | डांगावास, मेड़ता सिटी (नागौर)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

बजरी माफिया से सांठगांठ पर 1 1 पुलिस निरीक्षकों पर गाज गिरी

पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा ने प्रदेशभर में किया डिकॉय ऑपरेशन

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। प्रदेश में बजरी माफियाओं से सांठगांठ और गंभीर लापरवाही रखने वाले 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस सेंगाथिर के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा द्वारा डिकॉय ऑपरेशन करने के बाद यह कार्रवाई हुई।

प्रदेशभर में चलाए गए डिकॉय ऑपरेशन के बाद कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही और अवैध बजरी खनन में संलिप्तता पाए जाने पर गाज गिरी है। इस कार्रवाई में पांच पुलिस निरीक्षकों को तत्काल निलंबित किया गया है, जबकि छह अन्य को लाइन हाजिर किया

■ **पांच पुलिस निरीक्षक निलंबित, अन्य 6 को लाइन हाजिर किया**

गया है।

एडीजी सेंगाथिर ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गठित 11 विशेष टीमों ने 18 और 19 दिसंबर को राज्य के विभिन्न जिलों में गुप्त तरीके से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया। इन टीमों ने आम नागरिक बनकर पुलिस थानों की कार्यप्रणाली, नाकाबंदी और गश्त व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सामने

आया कि कई थानों में न केवल बजरी के अवैध परिवहन को नजरअंदाज किया जा रहा था,बल्कि ड्यूटी के प्रति भी भारी लापरवाही बरती जा रही थी।

जांच में दोषी पाए जाने पर 21 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने सख्त कदम उठाते हुए जयपुर दक्षिण जिले के शिवदासपुरा, टोंक के पीपलू व बरीनी, अजमेर के पीसांगन और धौलपुर के कोतवाली थाना अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही भीलवाड़ा के थाना गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाडी व नात्ता, दोसा के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगारार और जोधपुर पश्चिम के लूणी थाना अधिकारियों को

लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

बजरी माफिया के मददगारों के लिए विभाग में जगह नहीं : पुलिस मुख्यालय ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दोषी कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑपरेशन में दोषी मिले 11 थानों के 15

पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पीएचक्यू से आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर को निर्देश जारी किए गए हैं।

इससे पहले नवंबर माह में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो एफआईआर दर्ज न करने, परिवारियों से दुर्व्यवहार, साइबर क्राइम की शिकायतों पर हिलाई, एसपी ऑफिस में प्राप्त परिवारों में परिवाद अनुभाग की कार्यप्रणाली, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली एवं कार्यशैली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे बिंदुओं पर डिकॉय ऑपरेशन किया गया था।

बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह की शहादत के किस्से आमजन तक पहुंचायेगी भाजपा : टीटी



भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ‘वीर बाल दिवस’ कार्यक्रम प्रदेश समन्वयक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की।

के उद्देश्य से प्रदेशभर में मंडल से लेकर जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इसके साथ ही 26 दिसंबर को राजकीय विद्यालयों में एक घंटे के विशेष सत्र के दौरान बच्चों को वीरता और शहादत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रदर्शन करेंगे तथा साहित्यकारों की शहाबाद व किशनगंज प्रदर्शनी भी लगाएंगे, जिससे उनकी गौरवशाली गाथा जन-जन तक पहुंच सके।

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 2 5 साल पूर्ण हुए

जयपुर (कासं)। स्वतंत्रता के दशकों बाद तक भारत के ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। इन सुविधाओं तक पहुंचने के लिए एक मार्ग की जरूरत थी। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। जिसके तहत सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरुस्थलीय तथा आक्विफरी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर

इसमें प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य शामिल किया गया।

इसी लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गत 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किमी. से अधिक सड़कों का निर्माण किया और 15983 बसावटों/गांवों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा। यह केवल सड़कों का विस्तार नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और नये अवसरों को पहुंचाने की पहल रही है। चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण प्रदेश में पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण का

- **प्रदेश में 75 हजार से अधिक किलोमीटर सड़कें तथा 68 गुल बनाकर 15983 बसावटों को जोड़ा गया**
- **केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मेड़ता में 2089 करोड़ रुपये लागत की 1216 पीएमजीएसवाई सड़कों की सौगात देंगे**

आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय कृषि, कृषक सौगात देंगे। जिनकी अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ होगी।

गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश

में लगभग 12086 करोड़ रूपये की लागत से 49730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 14043 किमी. सड़कों के चौड़ाईकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य भी किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चर्यानित “शू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क” को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सिर्फ नयी सड़कों का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि मौजूदा सड़कों के नेटवर्क को और अधिक

मजबूत करना भी आवश्यक है। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 1103 करोड़ रुपये की लागत से 3468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौड़ाईकरण-सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। अब तक प्रदेश में 4060 करोड़ रुपये की लागत से 8549 किमी. की 903 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 पुलों का निर्माण किया, शेष कार्य प्रगतिरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम-जनमन योजना का शुभारम्भ किया था, जिसके तहत बारां की शहाबाद व किशनगंज ब्लॉक की सहरीया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत लगभग 11 करोड़ की लागत से 22 किमी. सड़क निर्माण कर 11 बसावटों को सड़कों से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है।

एम.एन.आई.टी. में प्रस्तावित ट्रेड फेयर पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एमएनआईटी परिसर में अगले माह प्रस्तावित सोलर ट्रेड फेयर को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एमएनआईटी निदेशक, राजस्थान सोलर एसोसिएशन, मुख्य सचिव और सीपीजे सहित अन्य को जवाब पेश करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश संयुक्त अभिवाक संघ की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

जनहित याचिका में अभिवक्ता विनोद कुमार वैष्णव ने अदालत को बताया कि जेएलएन मार्ग स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अगली 16 जनवरी से तीन दिवसीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सोलर क्षेत्र से जुड़ी प्रदेश की दर्जनों निर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियां भाग लेंगी। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और

- **बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से प्रस्तावित 3 दिवसीय इस ट्रेड फेयर में सोलर क्षेत्र से जुड़ी दर्जनों निर्माता और सेवा कंपनियां भाग लेंगी**
- **याचिका में कहा गया कि, “संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत विद्यार्थियों को शांत और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।”**

शुद्ध शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में व्यावसायिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि एमएनआईटी जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान के परिसर में इस तरह के व्यापारिक मेलों का आयोजन न केवल शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और गरिमा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि परिसर में बने हॉस्टल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रहते

है और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के प्रावधान हैं। ऐसे में बिना जांच पड़ताल कंपनियों से जुड़े लोगों को यहां प्रवेश देना उचित नहीं है। ऐसे में इस प्रस्तावित ट्रेड फेयर के आयोजन को रोका जाए। याचिका में पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी भारत व्यास व अन्य वकील उपस्थित हुए और उन्होंने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को रखते हुए पक्षकारों को जवाब पेश करने को कहा है।

रिलायंस ज्वैल्स की “ड्रीम डायमण्ड सेल” शुरू

मुंबई। रिलायन्स ज्वैल्स अपनी “ड्रीम डायमण्ड सेल” फिर से लेकर आए है, जिसके तहत उपभोक्ता आकर्षक एवं लुभावने तरीके से इस सीजन का ख़र्चन मना सकेंगे। यह सेल देश भर में 145 से अधिक रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स पर उपलब्ध है। आगामी 27 जनवरी 2026 तक चलने वाली यह सेल ऐसे समय में लाई जा रही है, जब लोग साल के अंत में उपहार खरीदते हैं, त्योहारों की खरीददारी करते हैं या किसी यादगार के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। इस साल की ड्रीम डायमण्ड सेल, हर किसी के लिए हीरों की खरीद को सुलभ बनाएगी। ग्राहकों को 25 हजार रु. के हीरों की हर खरीद पर 0.25 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। इस सीजन की सेल हीरा और सोना एक साथ खरीदने का अनूठा मौका मिलेगा। सेल के दौरान 75 हजार रु. की गोल्ड ज्वेलरी की खरीद पर मेकिंग चार्ज पर फ्लैट 20



फीसदी छूट मिलेगी। रिलायन्स ज्वैल्स स्टोर्स में ग्राहक, रोजमर्रा के लिए डायमण्ड ज्वेलरी जैसे ईयररिंग, रिंग, चेन या स्टेटेमेंट स्टायल जैसे चोकर और ब्राइडल डिजाइनों की खरीददारी कर सकेंगे।

जयपुर (कासं)। जयपुर आभूषण की दुनिया में एक विशिष्ट स्थान रखता है और जयपुर ज्वेलरी शो इस शहर की समृद्ध विरासत, परंपरा और कला का उत्सव है। यह बात राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर ज्वैलरी शो 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आभूषण उद्योग आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकार प्रातिशील नीतियों और ईए ऑफ दूइंग बिजनेस के जरिए इस उद्योग को सहयोग करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जेजेएस वार्ड्स चेयरमैन दिनेश खटोरिया ने कहा कि अपने शुरुआती

- **18 से 21 दिसंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा आगामी संस्करण**

वर्षों में मात्र 67 बूथों से शुरू होकर आज 1227 बूथों तक पहुंचना इस शो की उल्लेखनीय विकास यात्रा को दर्शाता है। आज यह एजीबिशन देश की सबसे बड़ा बी2बी और बी2सी प्लेटफॉर्म बन चुकी है।

जेजेएस के मानद सचिव राजीव जैन ने बेस्ट बूथ अवॉर्ड्स की घोषणा की। उत्कृष्ट बूथ डिजाइन और ज्वेलरी प्रस्तुति के लिए 18 वर्ग मीटर से ऊपर बेस्ट बूथ ज्वेलरी श्रेणी में विजेताओं में पहला स्थान बिरछीचंद घनश्याम दास ने जीता। दूसरे स्थान पर

मोहनलाल नारायणदास ज्वैलर्स रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी (आईआईजीसी) को बेस्ट इंस्टीट्यूट अवॉर्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने शो के अगले संस्करण की तारीखों की भी घोषणा की, जो 18 से 21 दिसंबर, 2026 तक आयोजित होगा। जैन ने बताया कि इस वर्ष शो में 46 हजार से ज्यादा विजिटर्स आए, जिनमें से 15 हजार बाहर के शहरों से थे।

जेजेएस के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता अजय काला ने समापन समारोह का संचालन किया। उन्होंने कहा कि इस बार जेजेएस व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधन की दृष्टि से भी व्यापक और उपयोगी शो रहा। उन्होंने शो की सफलता के लिए सभी प्रदर्शकों, चित्रेताओं और आगंतुकों का आभार जताया।

सार-समाचार फैशन और ज्योतिष का अब्दुत संगम



जयपुर । अलमाइटी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव (एआईएसी) सीजन-2 के अंतर्गत आयोजित लिविंग ज्योडिक फैशन शो ने फैशन और ज्योतिष के अब्दुत संगम को भव्य मंच पर प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अनूठे आयोजन में राशियों की ऊर्जा, रंगों और भावनाओं को फैशन के माध्यम से जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की संयोजक डॉ. मेधा शर्मा ने बताया कि यह भव्य आयोजन ऑलमाइटी इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल वास्तु अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। शो की परिकल्पना और निर्देशन, मिससे इंडिया इंटरनेशनल दीप्ति सैनी ने संभाली। इस विशेष फैशन शो में प्रीति सचदेवा, युविका जैन, मीनाक्षी सोलंकी, अमृता टांगीवाल, ममता जायसवाल, अंशु वाघवा और इंद्रजीत दास ने विभिन्न राशियों पर आधारित डिजाइनों को आत्मविश्वास, गरिमा और सौंदर्य के साथ रैप पर प्रस्तुत किया। प्रत्येक प्रस्तुति में संबंधित राशि के रंग, व्यक्तित्व और कॉस्मिक ऊर्जा का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिला। शो की विशेष आकर्षण रही शोर्ट्स पर आरजे देवांगना, जिन्होंने रैप पर अपनी दमदार उपस्थिति से समा बांध दिया। मंच पर मेघ की ऊर्जा, सिंह की शाही भव्यता, तुला का संतुलन और कर्क की कोमलता फैशन से सजीव हुई।

ब्राइट फ्यूचर स्कूल में क्रिसमस पर्व मनाया

जयपुर । जनता कॉलोनी स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ “क्रिसमस” पर्व मनाया। लाल और सफेद रंग की पोशाक पहनकर छोटे-छोटे बच्चों ने क्रिसमस कैरौल की धुन पर गाकर और नाचकर बुखियां फैलाई। अनर्गल छोटे सांता क्लॉज ने माहौल को जादुई बना दिया और वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार और मनमोहक पल बनाए। यह उत्सव हंसी, संगीत और एकजुटता की भावना से भरा था। उत्साह को बढ़ाते हुए, डायरेक्टर तेजेंद्र शर्मा और गौरव तेज शर्मा ने बच्चों को बेस्ट डॉसर, बेस्ट ड्रेस्ड, बेस्ट पोस्टर मेकर और अन्य कैटेगरी में पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

वीकेंड के बाद भी सरस राजसखी राष्ट्रीय मेले में रौनक बरकरार



जयपुर । सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला-2025 में वीकेंड के बाद भी उत्साह और चहल-पहल कम नहीं हुई। सोमवार को मेले के पाँचवें दिन सामान्य कार्यदिवस होने के बावजूद मेला परिसर में भीड़ देखने को मिली। शिल्प, हस्तकला और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने मेले को एक जीवंत उत्सव का रूप दे दिया।

परिवारों के साथ आए दर्शकों ने विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं के उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इसी क्रम में टाइनी टॉट्स इंग्लिश स्कूल के स्कूली बच्चों ने भी मेले का भ्रमण किया।

नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े तीन करोड़ रुपए बदलने से हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टबल जजमेंट में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इनकार किया, याचिकाएं खारिज की

जोधपुर, (कासं)। नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े तीन करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 500 और 1००0 रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये नोट अब रद्दी हो गए हैं।

बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 16 लाख रुपए के 500 और 1००0 रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए मार्च 2017 में याचिका लगाई थी। इसके अलावा बाद में 6 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) ने भी अपने पुरानी करेंसी के करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए बदलने के लिए अलग-अलग याचिका लगा दी थी। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह

■ **हाईकोर्ट ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनोर, बिसारनिया, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सभी याचिकाएं खारिज की**

भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति सहित 7 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक नीतियों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। आरबीआई द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लगाई गई रोक जनहित में लिया गया सही फैसला था। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि महज कठिनाई या असुविधा, चाहे वह कितनी ही वास्तविक क्यों न हो। किसी वैध आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए

उठाए गए नियामक उपायों को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकती।

16 लाख से ज्यादा की पुरानी करेंसी :-बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने याचिका में बताया था कि 8 नवंबर 2०16 को नोटबंदी की घोषणा के समय उनके पास 16 लाख 17 हजार 500 रुपए (5०0 और 1०00 के नोट) की नकदी मौजूद थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ये पैसा किसानों और आम लोगों का है, जो वैध तरीके से समिति के पास आया था लेकिन

आरबीआई ने 14 और 17 नवंबर 2016 को सर्कुलर जारी कर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुराने नोट स्वीकार करने से रोक दिया। वकील ने कहा कि एक ही तरह की अन्य सोसायटियों ने नोट जमा करवा दिए, लेकिन याचिकाकर्ता को अनुमति न देना भेदभावपूर्ण है। इस समिति के अलावा बामनोर, बिसरणि्या, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी के रूप में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के जरिए काम करने वाली समितियों ने भी अपने साढ़े तीन करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए याचिकाएं दायर की थीं। इनकी मांग थी कि 14 और 17 नवंबर 2016 के आरबीआई सर्कुलर को अवैध और आरबीआई एक्ट-1934

की धारा 26 (2) के खिलाफ घोषित कर रह किया जाए, ताकि ये समितियां अपने पुराने नोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से जमा करा सकें, या नाबाई को नोटों की जांच कर वैधानिक निपटान करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने पाया कि आरबीआई के सर्कुलर मनमाने नहीं थे, बल्कि वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि नाबाई की भूमिका केवल पर्यवेक्षी है। वह आरबीआई के बाध्यकारी निर्देशों के खिलाफ जाकर नोटों की जांच या निपटान की अनुमति नहीं दे सकता। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनोर, बिसारनिया, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी।

मारुति सुज़ुकी प्री-ओन्ड कार्निवल से ग्राहकों में उत्साह



कोटा। मारुति सुजुकी टू वैल्यू द्वारा कोटा में आयोजित प्री-ओन्ड कार कार्निवल शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान 200 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया और विभिन्न कारों का टेस्ट ड्राइव किया। कार्यक्रम में

फैमिली गैम्स और मनोरंजक गतिविधियों के कारण अच्छा फुटफॉल देखने को मिला। भाटिया एंड कंपनी एवं स्वालका मोटर्स द्वारा 1०0 से अधिक क्वालिटी सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कारों को प्रदर्शित किया गया, जिन पर 1 वर्ष अथवा 15

हजार किमी. वारंटी एवं 3 फ्री सर्विस की सुविधा दी गई। ग्राहकों के उत्साह को देखते हुए इस कार्निवल को 21 दिसंबर को भी जारी रखा गया। ज्ञात रहे कि वर्तमान में देशभर में 6० लाख से अधिक ग्राहक मारुति सुजुकी टू वैल्यू से जुड़े चुके हैं।

सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश

अलवर, (निस्)। अलवर में सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल में मृतकों के परिजन और पुलिस आमने-सामने हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नीलगाय से नहीं, बल्कि विजय मंदिर थाना पुलिस की 112 गाड़ी की टक्कर से हुआ है, जबकि पुलिस नीलगाय से टकराने से हादसा होने की बात कह रही है। इस पूरे मामले में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने भी पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ड्राइवर को बचाने में लगा है। हालांकि, विजय मंदिर थाना एसएचओ प्रेमलता वर्मा मौके पर पहुंची और परिजनों समझाइश की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की 112 गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दे दी है। जिसकी जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम सात बजे के आसपास जटियाना गांव के पास बहरोड़ रोड स्थित मोटल होटल के सामने की है। मृतक रामधन (32) निवासी अमृतवास और उसके चचेरे भाई शेर सिंह (33) के शव अभी तक जिला



मृतकों के फाइल फोटो।

- परिजन का आरोप है कि पुलिस जीप ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी थी**
- पुलिस नीलगाय से टकराने से हादसा होने की बात कह रही है, विजय मंदिर थाना एसएचओ प्रेमलता वर्मा मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की**

अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। हालांकि, थानाधिकारी की समझाइश के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्यवाई शुरू होने से पहले ही रोक दी गई।

सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा भी मौके पर पहुंची। परिवार की मांग है कि पहले पुलिस की गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कांपी दे, फिर

सांवलिया सेठ के एक माह के भंडार से 29.32 करोड़ का चढ़ावा मिला

मंडफिया, (निस्)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दरबार में गत 18 दिसंबर चतुर्दशी को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारि दास वैष्णव की उपस्थिति में चौथे चरणों में संपन्न हुई।

मंदिर अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने बताया कि चौथे चरण में हुई भंडार गिनती में 49 लाख 84 हजार 395 रुपए नगद प्राप्त हुए। इससे पूर्व तीन चरणों में हुई गिनती में 22 करोड़ 30 लाख 85 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों चरणों की गिनती को मिलाकर कुल 22 करोड़ 80 लाख 69 हजार 395 रुपए की नगद प्राप्त हुए। अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा भंडार से निकले सोने-चांदी का

तोल भी किया गया। भंडार से 1 किलो 250 ग्राम सोना व 44 किलो 400 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न भक्तों द्वारा मंदिर कार्यालय में 535 ग्राम 910 मिली ग्राम सोना व 55 किलो 444 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप जमा हुई। अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा विभिन्न भक्तों ने विभिन्न स्थानों से मनी ऑर्डर भेजकर,ऑनलाइन द्वारा एवं स्वयं उपस्थित होकर मंदिर कार्यालय में 6 करोड़ 51 लाख 35 हजार 525 रुपए भेंट जमा किए। भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के एक माह के भंडार एवं भेंट कक्ष कार्यालय से कुल 29 करोड़ 32 लाख 4 हजार 920 रुपए का नगद चढ़ावा मिला। भंडार गिनती में मंदिर अध्यक्ष वैष्णव, मंदिर बोर्ड सदस्य सहित मंदिर कर्मचारी एवं बैंक कर्मी उपस्थित थे।



भंडार गिनती में मंदिर अध्यक्ष, मंदिर बोर्ड सदस्य सहित मंदिर कर्मचारी एवं बैंक कर्मी उपस्थित थे।

तंत्र-मंत्र के नाम पर 10 लाख की ठगी, एमपी से आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं, (निस्)। जिले की मेहाड़ा पुलिस ने भूत-प्रेत का साया बताकर तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी बंगाली बाबा को गिरफ्तार किया है। यह बाबा बंगाल का नहीं, बल्कि हरियाणा का निकला, जिसके पीछे जब पुलिस पड़ी तो मेहाड़ा पुलिस की मध्यप्रदेश के एक मंदिर में मिला।

सीआई राममनोहर ने बताया कि सिहोड़ निवासी राजेश सोनी 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि उसके घर पर एक व्यक्ति बर्तन बेचने के बहाने आया था, जिसने उसके बड़े भाई नरहरि को देखा और कहा कि इस पर भूत-प्रेत का साया है। इसे दूर करने के लिए उसके पास एक महाराज हैं, जो बंगाल में रहते हैं, जिससे नरहरि एकदम ठीक हो जाएगा। राजेश सोनी उसकी बातों में आ गया। जिसके बाद बंगाली बाबा के नाम से महाराज शिवकांत शर्मा आया। उसने बताया कि पूरे घर पर तांत्रिक क्रिया की हुई है। इसके लिए अनुष्ठान आदि करना

- भूत-प्रेत का साया बताकर तंत्र-मंत्र के नाम पर 10 लाख की ठगी की थी**

पड़ेगा। करीब चार-पांच महीनों तक तंत्र मंत्र से बंगाली बाबा शिवकांत शर्मा में अनिष्ट की आशंका दिखाकर उससे और उसके रिश्तेदारों से करीब 10 लाख 10 हजार 840 रुपए ठग लिए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तो इस बंगाली बाबा की तलाश में पुलिस ने हरियाणा के निजामपुर, नांगल चौधरी, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, शिवपुरी, बधवास, कोलसर, खरोरा, अशोकनगर आदि जगहों पर तलाश की, लेकिन अंत में आरोपी मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के मौजा पिराही गांव में स्थित एक बालाजी मंदिर में मिला, जिससे लाकर

घने कोहरे में लिपटा सरवाड़ शहर

सरवाड़, (निस्)। शहर साहित उपखंड क्षेत्र में सर्दी के मौसम में पहली बार घना कोहरा छाने से सर्दी का असर देखने को मिला। वहीं कोहरे से खेतों में खड़ी फसलों को काफी फायदा साबित होगा। कोहरे के कारण वाहन चालकों व आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।सोमवार को सुबह से ही उपखंड क्षेत्र में घने कोहरे की चादर में

लिपटा हुआ नजर आया। वाहन चालकों को कोहरे के कारण हेडलाइट जलाकर रखना पड़ा। घने कोहरे के कारण खेतों में खड़ी फसल सरसों गेहूं चने साहित अन्य फसलों को इसका फायदा पहुंचेगा। भयंकर सर्दी ने आमजन को ठिठुराकर रख दिया इस दौरान अजमेर कोटा स्टेट हाईवे व देवली कोटा स्टेट हाईवे पर दूर-दूर तक सड़क नहीं दिखाई दी।

शिल्पग्राम उत्सव : विभिन्न राज्यों के लोक गायन और लोक नृत्यों ने धूम मचाई



शिल्पग्राम उत्सव में मुक्ताकाशी मंच पर विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने लोक गायन और लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी।

उदयपुर, (निस्)। 'लोक के रंग-लोक के संग' थीम को सोमवार को मुक्ताकाशी मंच पर विभिन्न राज्यों के लोक गायन और लोक नृत्यों ने साकार किया। इन प्रस्तुतियों को देखकर दर्शक मंत्र मुग्ध हो गए। वहीं, उत्सव के दौरान शिल्पग्राम के विभिन्न थडों पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां सुबह से शाम तक दर्शकों का मन मोह रही हैं। इसके साथ ही बंजारा मंच पर 'हिवाड़ा रो हुक' में जहां मेलाथिर्थों ने खुद प्रस्तुतियां देकर लुप्त उठाया, वहीं बीच-बीच में संचालक सोम भट्ट ने प्रश्नोत्तरी चलाकर प्रोग्राम को और रोचक बना दिया।

मुक्ता काशी मंच पर सोमवार शाम मुख्य कार्यक्रम में राजस्थान के मांगणियार गायन और सफेद आंगी गेर के साथ ही डेरू डांस ने सामयीन का दिल जीता, वहीं इस प्रोग्राम को ओडिशा के सभलपुरी डांस ने दिगुणित बना दिया।

बिलेठा में अवैध खनन और क्रेशर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

भीलवाड़ा, (निस्)। ग्राम पंचायत बिलेठा के ग्रामीणों ने खनिज विभाग भीलवाड़ा द्वारा जारी माइनिंग लीज 39/2००4 को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

ग्रामीणों ने मीडिया को बताया और आरोप लगाया कि मैसर्स अर्विन एग्रीगेटर के नाम से जारी यह लीज तथ्यों को छुपाकर और अधिकारियों से मिलीभगत कर हासिल की गई है। यह लीज पटवारा हल्का बिलेठा व पेयजल का प्रमुख स्रोत तालाब स्थित है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर लीज स्वीकृत की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्म द्वारा लीज क्षेत्र के अतिरिक्त आसपास की कृषि भूमि पर भी अवैध रूप से खनन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए किसानों पर दबाव बनाकर उनकी भूमि जबरन कब्जाने या औने-पौने दामों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर ग्रामीणों को डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि मार्बल

खनन के लिए ली गई लीज पर अवैध रूप से गिट्टी क्रेशर स्थापित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में उड़ने वाली धूल से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा और आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि बंजर होने की आशंका है। इससे ग्रामवासियों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर भारी नुकसान होगा।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लीज क्षेत्र के पास ही उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र स्थित है, जहां कई परिवार निवास करते हैं। खनन और क्रेशर संचालन से इस धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद ग्राम पंचायत बिलेठा से अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं की गई, फिर भी खनिज विभाग भीलवाड़ा ने माइनिंग लीज जारी कर दी। इस माइनिंग लीज को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

झुंझुनूं में जुआ खेलते चार जने गिरफ्तार

झुंझुनूं, (निस्)। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉम्प्लेक्स में दो हजार रुपए दिन का किराया लेकर खेल रहे जुआघर को पकड़ा है। साथ ही चार आरोपियों को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं फ्लेट के मालिक इमरान खान पुत्र इकराम काजी की भी जुआघर चलाने के मामले में आरोपी मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

शहर कोतवाल श्रवण कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोड नंबर तीन पर स्थित जन्नत कॉम्प्लेक्स के दूसरे फ्लोर के फ्लेट नंबर चार में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीाने ने मौके पर दबिश दी। जहां चार व्यक्ति

एकराय होकर अनाधिकृत रूप से जुआ खेलते पाए गए। पुलिस ने मौके से जुआ सामग्री एवं 4,6०,००० रुपए नकद जब्त कर शहर के थार्ड नंबर 32 पीनवी बैंक वाली गली रोड नंबर एक निवासी गुलाब पुत्र प्रभातीलाल कुमावत, मोहल्ला खोरा निवासी साजिद अली पुत्र कासम अली, फुटला बाजार निवासी सलीब अहमद पुत्र गुलाम हुसैन तथा गुढ़ा मोड़ रहमानिया मस्जिद के पास रहने वाले 60 वर्षीय अब्दुल रजाक पुत्र गनी खान जाति क्यामखानी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह फ्लेट इमरान खान का है, जिसकी अनुमति से वे पिछले 8-1० दिनों से यहां जुआ खेल रहे थे और इसके बदले प्रतिदिन 20०0 रुपए किराया दिया जा रहा था।

तीन दलित प्रोफेसरों को एपीओ करने पर नाराजगी

अलवर। प्रदेश में एक दलित डिप्टी सीएम, दलित आयुक्त हैं, फिर भी एक ही कॉलेज के तीन दलित प्रोफेसरों को एपीओ करने को लेकर नाराजगी जताई है। जानकारी के अनुसार बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में पदस्थापित डॉ. अशोक कुमार खटीक आचार्य भृगोल, डॉ.महेश चंद्र गोठवाल सहआचार्य लोक प्रशासन एवं सुंदर लाल बसवाल सहायक आचार्य इतिहास को उप शासन सचिव प्रथम के 19.12.2०25 के आदेश के तहत पदस्थान की प्रतीक्षा में अर्थात एपीओ किया गया है, जिसके लिए कोई भी कारण अंकित नहीं किया गया है। तीनों प्रोफेसर अनुसूचित जाति से

हैं और अध्ययन, अध्यापन, सहशैक्षिक गतिविधियां तथा प्राचार्य द्वारा समय समय पर प्रदत्त कार्य कुशलता के साथ संपादित करते रहे हैं। डॉ. अशोक कुमार खटीक 9०0०00 पुस्तकों वाले महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रभारी हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष की कमी के कारण पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं। डॉ. महेश चंद्र गोठवाल, लोक प्रशासन विभाग में एकमात्र शिक्षक हैं। शोध कार्य भी करवाते हैं। सुंदरलाल बसवाल बहुत ही सक्रिय एवं विद्यार्थियों में लोकप्रिय शिक्षक हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी एवं कई वर्षों से अनुशासन समिति के सदस्य रहे हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं।

</

